Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ग्रामीण विकास में जल संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन : शाजापुर जिले के सन्दर्भ में

रवि भिलाला*

* शोधार्थी (भूगोल) पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – विश्व स्तर पर प्रत्येक विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता है। भारत सहित अधिकांश विकासशील राष्ट्रों का समग्र राजकीय चिंतन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के आस-पास रहता है। किन्तु इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति परिलक्षित नहीं हुई है। चूंकि भारत एक विशाल वृहद जनसंख्या वाला विकासशील देश है। भारत विश्व में चीन के बाद जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनसंख्या का लगभग तीन-चौथाई भाग गाँव में निवास करता है, जिसका जीवनयापन करने का मुख्य आधार कृषि तथा कृषि पर आधारित व्यवसाय और प्राथमिक लघु उद्योग है। इस लिए आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में ग्रामीण विकास को महत्व दिया जाता रहा है।

भारतीय ग्राम्य जीवन की जब भी बात होती है तो **'तपती हुई धूप में खेती करता हुआ किसान, दूर-दूर तक फैले खेत और उन पर लहराती हरी-भरी फसलें, घर का कार्य संभालती हुई महिलाएँ तथा हाट बाजार व मैले के दृष्य स्वत: ही मनमस्तिष्क पर उभर जाते हैं।'** किन्तु इक्कीसवीं सदी में ग्राम्य जीवन का दृष्य बिलकुल अलग है। वर्तमान में किसान की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्तमान में ग्रामिणों का जीवन धनी एवं निर्धन दो वर्गों में विभाजित है। भारतीय किसानों का बहुत बड़ा वर्ग आज निम्न स्तर का जीवनयापन कर रहा है। जनसंख्या के इस वर्ग के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने की आवष्यकता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इस धनी-निर्धन वर्ग में विभाजित अंतर को समाप्त किया जा सके एवं ग्रामवासियों का विकास हो सके।

भारत जैसे विकासशील देश का आर्थिक परिवर्तन मुख्यत: कृषि एवं इससे सहायक क्षेत्रों पर निर्भर करता है। जिसमे जल संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रोजगार अवसरों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहने वाली भारतीय जनसंख्या का अनुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा है। अधिकतम 70 प्रतिशत ग्रामिण जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए मुख्यत: कृषि पर निर्भर रहती है। भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है। जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है, जिसका भारत में प्राकृतिक उपयोग करके आर्थिक विकास किया जा सकता है भारत के आर्थिक विकास में विभिन्न तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है जिसमें जल संसाधनों का उल्लेख भी शामिल है।

ग्रामीण विकास की अवधारणा : ग्रामीण विकास की अवधारणा का इतिहास भारत में अत्यंत प्राचीन है। भारत प्राचीन काल से ही गांवों का देश रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यत: ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था है। प्रारंभ से ही ग्रामीण जनता की आवश्यकताएँ व साधन सीमित रहे हैं। जिनकी पूर्ति प्राथमिक साधन व ग्रामीण उत्पादन द्वारा हो जाती है। ग्रामीण विकास की अवधारणा का सुत्रपात महात्मा गाँधी के इस कथन से हुआ है **'भारत की आत्मा गावों में बसती है, जब तक गाँवों का विकास नहीं होता तथा गाँव पुन: आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता।'** इसी के आधार पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई।

ग्रामीण विकास : ग्रामीण विकास का अर्थ जानने के लिए गाँव तथा विकास का अर्थ जानना आवश्यक है। विकास में मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। अत: आर्थिक विकास का संबंध मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से है।

एक सामुदायिक इकाई जहां एक निश्चित संख्या में लोग निवास करते हैं। गाँव कहलाता है। 5000 से कम जनसंख्या जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो तथा जनसंख्या धनत्व 900 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलो मीटर से कम हो उसे ग्रामीण क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। यदि जनसंख्या 5000 से अधिक हो तथा उस क्षेत्र के अधिकांश लोगों का व्यवसाय खेती हो तो उसे भी गाँव कहा जाता है।

परिभाषा :

'ग्रामीण विकास एक ऐसी रणनीति है जो विशेष समूह के लोगों निर्धन ग्रामीण लघु एवं सीमांत कृषकों, काष्तकारों तथा भूमिहीनों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में सुधार करती है।' **-विश्व बैंक**

'ग्रामीण विकास लोगों के एक विशिष्ठ समुह (ग्रामीण निर्धनों) के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए अपनाई गई व्यूह-रचना है। इस व्यूह-रचना में लघु कृषकों, काश्तकारों तथा भूमिहीन कृषकों के समूह को शामिल किया जाता है।' **-अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD)**

अध्ययन क्षेत्र : प्रशासनिक दृष्टि से शाजापुर जिला उज्जैन संभाग का एक भाग है, जो मध्य-प्रदेश राज्य के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित है। पुरा जिला क्रिटेशियस युगीन दक्कन-ट्रेप का एक हिस्सा है। शाजापुर जिला क्षेत्र चित्रण की वर्तमान योजना के अनुसार मध्य-प्रदेश पठार, रतलाम पठार, पर बसा है। शाजापुर जिला मध्य-प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। जो

भौगोलिक दृष्टि से 30''06'से 24''19' उत्तरीय अक्षांश तथा 75''41' से 77''02' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। शाजापुर जिला पश्चिम में उज्जैन एवं अगर-मालवा दक्षिण में देवास उत्तर में राजगढ़ तथा पूर्व में सीहोर से घिरा हुआ है।

वर्तमान में इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3460.4 वर्ग किलोमीटर है। शाजापुर जिले की समुद्र तल से ऊँचाई 453 मीटर है, व सर्वाधिक ऊँची चौटी भैरव पहाड़ी (भैरव डुगरी) है, जो जिले के पश्चिम भाग में स्थित है। भैरव पहाड़ी की ऊँचाई 608 मीटर है। 1981 की जनगणना के दौरान शाजापुर जिला उज्जैन संभाग में लाया गया था। और जिला मुख्यालय को शाजापुर कहा गया। वर्तमान मे शाजापुर जिला राष्ट्रिय राजमार्ग 52 पर बसा है, जिसे पुर्व मे आगरा-बाम्बे रोड या (A.B.) रौड़ या राष्ट्रिय राजमार्ग 3 के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शाजापुर की जनसंख्या 94,1403 जिसमें पुरुष जनसंख्या 48,7468 व महिला जनसंख्या 45,3935 है। जिले में 76,5184 ग्रामीण तथा 17,6219 नगरीय जनसंख्या है। जिले का जनसंख्या घनत्व 244 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच 17.17% रहा।

तालिका 1 – शाजापुर जिला : तहसीलवार भौगोलिक स्थिति

क्र.	जिला/तहसील	उत्तरी अक्षांश विस्तर	पूर्वी देशांतर विस्तार	समुद्र तल से ऊँचाई
1	शाजापुर	23''06' से 24''19'	75''41' से 77''02'	453
2	तहसील शजापुर	23''11' से 23''44'	76''07' से 76''34'	453
3	मोहन बड़ोदिया	23''17' से 23''43'	75''19' से 76''08'	447
4	शुजालपुर	23''06' से 23''32'	76''28' से 76''51'	448
5	कालापीपल	23''06' से 23''31'	76''38' से 77''02'	492
6	गुलाना	23'40' से 10'00'	76'09' से 79'10'	466
7	पोलायकला	23'12' से 42'00'	76'33 से 08'00'	460

अध्ययन के उद्देश्य : शोधा के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

1. ग्रामीण विकास के लिए जल संसाधनों की आर्थिक भूमिका का अध्ययन करना है।
2. शाजापुर जिले के जल संसाधनों की वर्तमान उपलब्धता का अध्ययन करना है।
3. शाजापुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का अध्ययन करना है।

आंकड़ों का संकलन : किसी भी सामाजिक अनुसंधान के लिए विभिन्न प्रकार के तथ्यों या सूचनाओं के संकलन की आवश्यकता होती है। आंकड़ों व समकों का संकलन सामाजिक अनुसंधान की आधारभूत क्रिया है। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों, भारतीय जनगणना रिपोर्ट, संबंधित विषय पर शोध ग्रंथ, केंद्र एवं राज्यों के रिकॉर्ड, और जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला जल संसाधन विभाग, जिला सांख्यिकी कार्यालय, जिला चिकित्सालय, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, नगर पालिका परिषद, ग्रामीण विकास समितियां, कृषि एवं संबंधित सेवाएं, जिला उद्योग केंद्र, सामाजिक सेवाएं, जिला योजना विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग आदि के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

सांख्यिकी विश्लेषण : अध्ययन क्षेत्र के प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए उचित सांखिकीय विधियों को अपनाया गया है। मुख्यत: बाजार मूल्यांकन विधि, सूखात्मक आकलन, अविवेक मूल्यांक, प्रतिपगमन विश्लेषण, समांतर माध्य, माध्यिका, आदि विधियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किए गए है।

शाजापुर जिले में ग्रामीण विकास : शाजापुर जिला एक कृषि प्रधान तथा ग्रामीण जिला है, इसलिए जिले का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित ही है। शाजापुर जिले में समय-समय पर विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम से विकास को बढ़ावा दिया गया है। और पंचवर्षीय योजना काल में जिले में कृषि को राजनितिक महत्व मिला जिससे कृषि के क्षेत्र में नवीन बदलाव आए और ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। जिले में गेहूं, बाजरा, मौसमी सब्जियां, ज्वार, आदि की खेती की जाती है जो जिले की आर्थिक स्थिति का मुख्य साधान है।

ग्रामीण विकास को प्रभावित करने वाले कारक : जिले की जनसंख्या का व्यवसाय कृषि पर निर्भर करता है। कृषि का उत्पादन प्रभावित होने से जिले की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। शाजापुर जिले में ग्रामीण विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। निर्धानता ग्रामीण विकस को प्रभावित करने वाले करको मे से सबसे प्रमुख करक है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी, शिक्षा एवं तकनिकी ज्ञान का अभाव, आर्थिक असमानता, संसाधनों की कमी, स्थानिय राजनीतिक प्रभुत्व, भोतिक सुख सुविधाएँ आदि कारक है। जो ग्रामीण विकास को प्रभावित करते है।

ग्राम विकास के स्तर : ग्रामीण विकास एवं बहुआयामी अवधारणा है जिसका विश्लेषण दो दृष्टिकोणों के आधार पर किया गया है। संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टि से ग्रामीण विकास का अभिप्राय है विविध कार्यक्रमों, जैसे- कृषि, पशुपालन, ग्रामीण हस्तकला एवं उद्योग, ग्रामीण मूल संरचना में बदलाव, आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। वृहद दृष्टि से ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण जनों के जीवन में गुणात्मक उन्नति हेतु सामाजिक, राजनितिक, सांस्कृतिक, प्रोद्योगिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन करना।

शाजापुर जिले में जल संसाधन के स्त्रोत : शाजापुर जिले में जल संसाधन के पर्याप्त स्त्रोत है। लखुन्दर नदि, छोटी कालीसिंध नदि, बड़ी कालीसिंध नदि, चिल्लर नदि, नेवज नदि, छोटे-छोटे तालाब, कुए, कुण्डी, ट्यूब बेल, हैंड पम्प, नल कूप, बोरिंग, स्तानीय झीलें अदि के रूप में उपलब्ध है। एवं भूमिगत जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच पाया जाता है। भूजल एक मीठे पानी के स्त्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है, जिसका उपयोग जिले में हेंड पम्प, कुए, ट्यूबवेल, कुण्डी अदि के माध्यम से निकाल कर किया जा रहा है। जिले में भूमिगत जल का उपयोग ग्रामीण एवं नगरिया क्षेत्रों में घरेलु स्तर पर हेंड पम्प, कुए, ट्यूबबेल, कुण्डी अदि के माध्यम से दोष पूर्ण तरीके से दोहन किया जा रहा है। जिससे जिले में भूमिगत जल की उपलब्धता में कमी आने लगी है इसका एक मुख्य उदाहरण जिले की मोहन बडोदिया तहसील है, जहाँ भूमिगत जल पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर है।

शाजापुर जिले में जल संसाधन का वितरण : देश में वर्तमान में जल संसाधन का वितरण करना एक जटिल समस्या बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले वर्षों की तुलना में जल संकट बढ़ता जा रहा है। समस्या केवल गिरते भू-जल स्तर की नहीं बल्कि उसके प्रदूषित होने की भी है। शाजापुर

जिले में जल संसाधन का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में जिले की नदियों के माध्यम से किया जाता है। शाजापुर जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से जल संसाधन का वितरण किया जाता है। जिले की निचली तहसीलों में भूमिगत जल संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता है। किन्तु जिले की उंचाई वाली तहसीलों में भूमिगत जल संसाधन समाप्त होने की कगार पर है। जिले की मोहन बड़ोदिया तेहसिल इसका एक उदाहरन है जहा भूमिगत जल संसाधन 800 फिट के निचे चला गया है जो हमारे लिए विचारात्मक समस्या है। जिले में नगरिया क्षेत्र में जल का वितरण नगर के मुख्य जल स्त्रोत चीलर नदि पर बने बांध के द्वारा किया जाता है। यह बांध पैय जल के अतिरिक्त सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध करता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बांध पर बनी नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए जल उपलब्धा कराया जाता है।

जल संसाधन प्रबंधन और नियोजन : शाजापुर जिला एक कृषि उत्पादक जिला है। यहाँ मुख्यत: सोयाबीन, गेहूं, चना आदि फसलें बोई जाती हैं। जिले में जल संसाधनों के लिए पर्याप्त स्त्रोत हैं, जिनके माध्यम से कृषि की जाती है। यहाँ पर लघु एवं कुटिर उद्योग है। जो जल स्त्रोत के निकट स्थित हैं। जिले में बने बांध और तालाबों से पानी की समस्या का कुछ समय के लिए निराकरण तो होता है लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रो में अपर्याप्त है। हमें जल की प्राप्ति वर्षा के माध्यम से, तालाबों से, बांधों से, कुओं व नलकूप, आदि के माध्यम से होती है। देश में वर्षा का असमान वितरण है। इस पारिस्थि में कही बाढ़ तो कहीं सुके की समस्या बनी रहती है। जल संरक्षण एवं विकास वर्षा की बूँद का पृथ्वी पर गिरने के साथ ही करना चाहिए। इस हेतु नदी मार्गो पर बांधों एवं जलाशयों का निर्माण करना होगा ताकि भविष्य में हमें पीने को शुद्ध पेयजल, सिंचाई, मत्स्यपालन एवं औद्योगिक कार्यो हेतु जल उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही बाढ़ों से मुक्ति मिल सके एवं कम वर्षा, नीचे जल स्तर, सूखा ग्रस्त एवं अकालग्रस्त क्षेत्रों में नहरों आदि में जल की पूर्ति हो सके।

शाजापुर जिले में जल संसाधन का आर्थिक मूल्यांकन : आर्थिक मूल्यांकन का अर्थ है किसी संसाधन के उपयोग से प्राप्त लाभ और लागत का आकलन करना। जल संसाधनों के संदर्भ में यह निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है।

जल संसाधन का आर्थिक मूल्यांकन

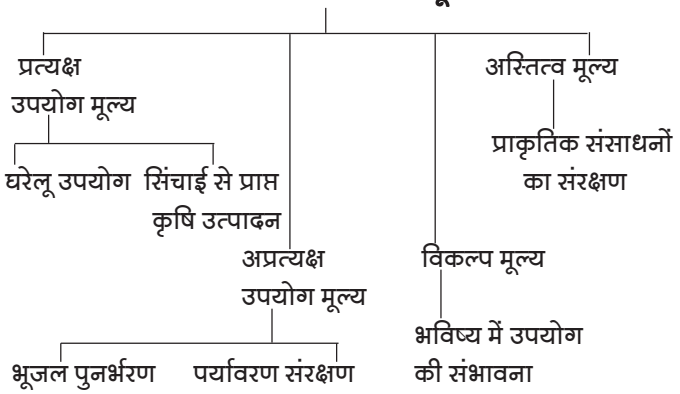

1. **कृषि उत्पादकता पर प्रभाव :** जल की उपलब्धता के कारण फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए सिंचित भूमि पर गेहूँ की उत्पादकता अधिक होती है।
2. **भूजल का दोहन :** शाजापुर में नलकूपों की संख्या बढ़ रही है, जिससे भूजल स्तर गिर रहा है। यह दीर्घकालीन आर्थिक हानि का कारण बन सकता है।
3. **तालाब और जल संरक्षण संरचनाएँ :** पारंपरिक तालाब जल संरक्षण का महत्वपूर्ण साधन हैं। इनका पुनर्जीवन आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकता है। और जल की उपलब्धता से कृषि उत्पादन बढ़ता है, जिससे आय बढ़ती है। सिंचाई सुविधाओं के कारण किसान बहुफसली खेती कर सकते हैं।
4. **लागत-लाभ विश्लेषण :** जल संरचनाओं पर खर्च (लागत) और उससे प्राप्त लाभ (उत्पादन, रोजगार) का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

निष्कर्ष : अध्ययन क्षेत्र में जिन गावों में जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, वहां ग्राम वासियों की आर्थिक दशा अच्छि है। एसे गावों में किसानों द्वारा साल में तिन बार फसल उत्पादन कीया जा रहा है। तथा वे लोग जल आधारित व्यवसाय में भी संलग्न है। शोध के दोरान पाया गया है, की शाजापुर जिले में जल संसाधन की उपलबता जिले की जनसँख्या, कृषि कार्य व उद्योगों की आवश्यकता के हिसाब से कुछ हद तक पर्याप्त है, लेकिन जिले में जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल समस्या की स्थिती बनी है। जिले का औसत भूमिगत जलस्तर 37 मीटर है। किन्तु जिले का जलस्तर प्रति वर्ष गिरता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। जिले की मोहन बडोदिया तहसील और मक्सी की ग्राम पंचायत झोंकर का भू-जलस्तर जिले में सर्वाधिक निचले स्तर पर है। झोंकर में 700 फीट की गहराई में भी पानी नहीं मिल रहा है। यहां जलस्तर निचे गिरने से नल-जल योजना भी बंद पड़ी है। ग्राम पंचायत झोंकर में टेंकरों से जल की पूर्ति की जाती है। मोहन बडोदिया तहसील का भी जलस्तर 42 मीटर से भी निचे चला गया है यदि जिले में जल के अति दोहन को रोका नहीं गया तो जिले के ये दो स्थान मरुस्थल में बदल जायेंगे।

सुझाव :

1. ग्राम वासियों को ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं की समय-समय पर जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए।
2. जल संसाधन के महत्व को बताते हुए उसके सही ढंग से उपयोग को बताना चाहिए।
3. शाजापुर जिला एक कृषि प्रधान जिला है, इसलिए शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं द्वारा कृषि से संबंधित नई तकनीकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना चाहिये।
4. ग्रामीण महिलाओं को घरेलू उद्योगों का प्रशिक्षण देना चाहिए।
5. स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे लघु उद्योगों का संचालन करना चाहिए जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल सके।
6. यदि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए प्रयास किया जाए एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो ग्रामीण पलायन को रोका जा सकता है।
7. शाजापुर जिला वनों के मामलों में शुन्य क्षेत्र जिला है, इस कारण जिले का भू-जलस्तर प्रति वर्ष गिरता जा रहा है। अत: जिले में जन सहयोग के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए।
8. जिले के कई ग्रामीण क्षेत्र एसे है, जहाँ ग्रीष्म काल में भूमिगत जल निचले स्तर पर चला जाता है। अत: एसे क्षेत्रों में जल प्रबंधान की उचित व्यवस्था करना चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मामोरिया चतुर्भुज एवं सिसोदिया एम. एस. (2007), पर्यावरण एवं विकास, साहित्य भवन आगरा।
2. खुल्लर डी. आर. (2017), भूगोल, Mc Graw Hill Education
3. डॉ. निमोले मोहन एवं डॉ. बघेल प्रमिला (2014), ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जल संकट नियोजन एवं प्रबंधन, अक्षरविन्यास उज्जैन।
4. जिला भू-अभिलेख कार्यालय, शाजापुर (म.प्र.)
5. जिला सांखिकीय पुस्तिका (2016), (2017), (2018), शाजापुर (म.प्र.)

****